



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1154]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 30, 2006/आश्विन 8, 1928

No. 1154]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 30, 2006/ASHVINA 8, 1928

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2006

का.आ. 1644(अ).—बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उप-धारा (7) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपधारा के उपबंधों के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा मंजूर दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन की योजना के संबंध में 03 अक्टूबर, 2006, को निर्धारित तारीख के रूप में विनिर्दिष्ट करती है।

[फा. सं. 15/7/2006-बीओए (i)]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

(BANKING DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2006

S.O. 1644(E).—In pursuance of sub-section (7), of section 45 of Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government hereby specifies the 3rd day of October, 2006 as the prescribed date in relation to the Scheme for the amalgamation of The United Western Bank Limited with Industrial Development Bank of India Limited which has been sanctioned by the Central Government under the provisions of said sub-section.

[F.No. 15/7/2006-BOA(i)]

AMITABH VERMA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2006

का.आ. 1645(अ).— केन्द्रीय सरकार ने बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45 की उप धारा (1) के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर उक्त धारा की उपधारा (2) के अधीन दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, सतारा, महाराष्ट्र के संबंध में एक अधिस्थगन-आदेश जारी किया है ;

और अधिस्थगन की अवधि के दौरान, भारतीय रिजर्व बैंक ने यह समाधान होने पर कि लोकहित में तथा निक्षेपकर्ताओं के हित में ऐसा करना आवश्यक है, उक्त अधिनियम की धारा 45 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड में समामेलन की एक स्कीम तैयार की थी ;

और भारतीय रिजर्व बैंक ने उक्त धारा की उपधारा (6) के उपबंधों के अनुसार उक्त स्कीम का प्रारूप संबंधित बैंकों को भेज दिया था तथा उक्त स्कीम के संबंध में प्राप्त सुझावों और आक्षेपों पर विचार करने के पश्चात् स्कीम को मंजूरी हेतु सरकार के पास भेज दिया था ;

अतः, अब केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 45 की उप धारा (7) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसके पश्चात् उल्लिखित निबंधनों और शर्तों पर उनके अधीन, निम्नलिखित स्कीम को मंजूरी देती है।

अध्याय-I

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड, (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन) स्कीम, 2006 है।

(2) यह उस तारीख को जिसे केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे प्रवृत्त होगी।

2. **परिभाषाएं :** इस स्कीम में, जबतक कि अन्यथा अपेक्षित न हो -

(1) "अधिनियम" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) अभिप्रेत है।

(2) "आस्ति खाता" से स्कीम में यथा उपबंधित नोशनल अंतरक बैंक के दायित्वों को समय-समय पर समायोजित करने के पश्चात् अधिशेष अथवा कमी को सुनिश्चित करने के लिए स्कीम के पैरा 5 के उप पैरा (2) के अनुसरण में खोला गया अभिप्रेत है ;

(3) "संग्रहण खाता" से वह सैद्धान्तिक खाता अभिप्रेत है जो आस्तियों और दायित्वों के समायोजन के बाद अंतरक बैंक के सदस्यों को वितरण के लिए उपलब्ध होनेवाली राशि को, यदि कोई हो, सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु स्कीम के पैरा 7 के अनुसरण में खोला गया हो।

- (4) "विहित तारीख से वह तारीख अभिप्रेत है जिसे पैरा 1 के उप पैरा (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार विनिर्दिष्ट करे।
- (5) "स्कीम" से दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड (इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड के साथ समामेलन) स्कीम, 2006 अभिप्रेत है ;
- (6) "अंतरक बैंक" से दि युनाइटेड वेस्टर्न बैंक लिमिटेड अभिप्रेत है जो एक बैंककारी कंपनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय सतारा, महाराष्ट्र-415001 में है;
- (7) "अंतरिती बैंक" से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक आफ इंडिया लिमिटेड अभिप्रेत है जो एक बैंककारी कंपनी है जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय आईडीबीआई टावर्स, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ परेड, मुम्बई-400005 में है ;
- (8) उन शब्दों और पदों का, जो इस स्कीम में प्रयुक्त है किन्तु परिभाषित नहीं किया गया है परंतु उक्त अधिनियम में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उक्त अधिनियम में है।

अध्याय - 2

कारबार, संपत्तियों, आस्तियों और दायित्वों का अंतरण

3. आस्तियों और दायित्वों का अंतरण तथा उसका साधारण प्रभाव :

(1) विहित तारीख से ही अंतरक बैंक के सभी अधिकार, शक्तियां, दावे, मांगें, हित, प्राधिकार, विशेषाधिकार, फायदे, आस्तियां और स्थावर तथा जंगम संपत्तियां, जिनमें परिसर सम्मिलित हैं, जो पट्टे या करारों में आरक्षित या अंतर्विष्ट किराए या अन्य धनराशि और प्रसंदिदा की आनुषंगिक अवधि, जिसके अधीन ये धारित है, तथा कार्यालय के सभी फर्नीचर, खुले रखे गये उपकरण, संयंत्र, उपकरण और साधन-सामग्री, बहियां, कागजात, लेखन-सामग्री का स्टॉक, अन्य स्टॉक और भंडार, स्टॉक, शेयरों और प्रतिभूतियों में सभी विनिधान निवेश, हाथ में तथा मार्गस्थ सभी प्राप्य बिल, हाथ में समस्त नकदी तथा बैंकों में चालू अथवा जमा खाते (जिसमें मांग अथवा अल्पकालिक सूचना पर देय/प्राप्य धनराशि सम्मिलित है), सोना-चांदी, सभी बही ऋण, बंधक ऋण तथा उनके लिए प्रतिभूतियों अथवा किसी गारंटी के फायदे सहित यदि कोई हो, अन्य ऋण, सभी अन्य संपत्ति, अधिकार और आस्तियाँ, अंतरक बैंक के कारबार के संबंध में सभी गारंटियों का लाभ, इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन अंतरिती बैंक को अंतरित मानी जायेंगी तथा वे उसकी संपत्तियां और आस्तियां होंगी और निर्धारित तारीख से अंतरक बैंक के सभी दायित्वों, शुल्क और बाध्यताएं यहां आगे दी गयी सीमा तक और ढंग से अंतरिती बैंक के दायित्व, शुल्क और बाध्यतायें होंगी।

(2) पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सभी संविदाएं, विलेख, बंधनत्र, करार, मुख्तारनामे, विधि का प्रतिनिधित्व की मंजूरियां तथा किसी भी स्वरूप के विद्यमान अथवा विहित तारीख से

ठीक पहले प्रभावी अन्य लिखत इसके पश्चात् बतायी गयी सीमा तक और ढंग से अंतरिती बैंक के विरुद्ध या पक्ष में प्रभावी होंगे तथा उन पर इस तरह से कार्रवाई की जाएगी मानो अंतरक बैंक के स्थान पर अंतरिती बैंक उनकी एक पक्षधर हो अथवा मानो वे अंतरिती बैंक के पक्ष में जारी किये गए हों।

- (3) यदि विहित तारीख को कोई वाद, अपील या किसी भी तरह की कोई अन्य विधिक कार्यवाहियां अंतरक बैंक द्वारा अथवा उसके विरुद्ध लंबित हो तो उनका उपशमन नहीं होगा या उसको रोका नहीं जायेगा अथवा किसी भी प्रकार से उस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, किन्तु वह इस स्कीम के अन्य उपबंधों के अधीन होगी और अंतरिती बैंक द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अभियोजित और प्रवर्तित होगी।

परन्तु जहां किसी अधिनियम के किसी भी उपबंध अथवा उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, विनियम, निर्देश अथवा आदेश का उल्लंघन किया जाता है अथवा विहित तारीख से पूर्व अंतरणकर्ता बैंक के निदेशक अथवा सचिव, प्रबंधक, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के विरुद्ध कोई दण्डनीय अपराध संस्थित किया गया है, तो ऐसे निदेशक, सचिव, प्रबंधक, अधिकारी अथवा अन्य कर्मचारी के विरुद्ध साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के लागू होने पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना किसी अन्य विधि में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, ऐसी विधि के अधीन कार्यवाही की जाएगी तथा तदनुसार ही उन्हें दण्ड दिया जाएगा।

- (4) यदि भारत से बाहर किसी देश के विधियों के अनुसार इस स्कीम के उपबंध उस देश में स्थित किसी आस्ति अथवा दायित्व के, जो अंतरक बैंक के कारबार का या अंतरिती बैंक के दायित्व का भाग हो, अंतरण अथवा उसको निहित करने के लिए स्वयं में प्रभावी न हों तो ऐसी आस्ति अथवा दायित्व के संबंध में अंतरक बैंक के मामले विहित तारीख को अंतरिती बैंक के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सौंपे समझे जाएंगे और मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऐसी आस्तियों के अंतरण और दायित्वों का प्रभावशाली ढंग से पालन करने के प्रयोजन हेतु सभी शक्तियों का उसी प्रकार प्रयोग करेगा जैसे कि वे अंतरक बैंक द्वारा प्रयोग की गयी हों। मुख्य कार्यपालक अधिकारी इस प्रकार के अंतरण को प्रभावी बनाने अथवा निहित करने के प्रयोजन हेतु ऐसे सभी कदम उठायेगा जो भारत से बाहर उस देश की विधि द्वारा अपेक्षित हों और उसके संबंध में मुख्य कार्यपालक अधिकारी या तो स्वयं अथवा उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से अंतरक बैंक की किसी भी आस्ति की वसूली करेगा अथवा उसके दायित्व का निर्वहन करेगा तथा शुद्ध आगम को अंतरिती बैंक को अंतरित करेगा।

4. अंतरक बैंक की बहियां बंद करना और तुलनपत्र तैयार करना :

- (1) अंतरक बैंक की बहियां बंद कर दी जायेंगी और उनका तुलन किया जायेगा तथा पहली बार उनका तुलनपत्र तारीख 02 सितम्बर, 2006 को कारोबार बंद होने के समय की स्थिति के अनुसार तैयार किया जायेगा और उसके बाद विहित तारीख के ठीक पहले की तारीख को कारोबार बंद करने की स्थिति के अनुसार तैयार किया जायेगा और उक्त तुलनपत्र की लेखा-परीक्षा और उसका प्रमाणीकरण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए अनुमोदित या नामनिर्देशित किसी चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट अथवा चार्टर्ड अकाउन्टेन्टों की किसी फर्म से करवाया जायेगा।

(2) पूर्वगामी पैरा के उपबंधों के अनुसार तैयार किये गये अंतरक बैंक के तुलनपत्र की प्रति उसके प्राप्त होने के पश्चात् यथाशीघ्र अंतरक बैंक द्वारा कंपनी रजिस्ट्रार को प्रस्तुत की जायेगी और उसके बाद अंतरक बैंक को तुलनपत्र अथवा लाभ-हानि खाता तैयार करने अथवा उसे सदस्यों को प्रस्तुत करने अथवा कंपनी रजिस्ट्रार को प्रतियां प्रस्तुत करने अथवा तुलनपत्र और खातों पर विचार करने या किसी अन्य प्रयोजन हेतु अथवा कंपनी अधिनियम 1956 (1956 का 1) की धारा 159 के उपबंधों के पालन के लिए बोर्ड की बैठक या वार्षिक साधारण सभा बुलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी तथा उसके बाद अंतरक बैंक के निदेशकों के लिए उक्त कंपनी अधिनियम की धारा 285 की अपेक्षानुसार बैठक करने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

5. आस्तियों का मूल्यांकन और दायित्वों का निर्धारण:-

अंतरिती बैंक अंतरक बैंक के परामर्श से निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार अंतरक बैंक की आस्तियों का मूल्यन करेगा और अंतरक बैंक की दायित्वों की, गणना करेगा, अर्थात् :

(1)(क) सरकारी प्रतिभूतियों के भिन्न विनिधानों का मूल्यन विहित तारीख से ठीक पूर्व दिन प्रचलित बाजार दर पर किया जायेगा ;

(i) सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्यांकन बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 24 के प्रयोजन हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गयी अधिसूचना में निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार, विहित तारीख के ठीक एक दिन पहले की स्थिति के अनुसार किया जायेगा ;

(ii) केन्द्रीय सरकार की अल्प बचत योजना के अधीन जारी किये गये डाकघर प्रमाणपत्रों, खजाना बचत जमा प्रमाणपत्रों तथा किन्हीं अन्य प्रतिभूतियों, प्रमाणपत्रों जैसी केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों का मूल्यांकन उनके अंकित मूल्य अथवा उस तारीख को नकदीकरण योग्य मूल्य, इनमें से जो भी उच्चतर हो, पर किया जाएगा ;

(iii) जहां अंतरक बैंक द्वारा धारित जमींदारी उन्मूलन बंधपत्रों जैसी किसी सरकारी प्रतिभूति अथवा इसी प्रकार की किसी अन्य प्रतिभूति के बाजार मूल्य को, जिसके संबंध में मूलधन का भुगतान किस्तों में किया जाना है, सुनिश्चित नहीं किया जा सकता अथवा किसी अन्य कारण से बाजार मूल्य को उसका सही मूल्य नहीं माना जा सकता है अथवा अन्यथा उचित नहीं माना जा सकता है, उस दशा में उस प्रतिभूति का मूल्यांकन मूलधन की किस्तों और संदाय करने के लिए शेष ब्याज, इस प्रकार की किस्तों के देय रहने की अवधि, जिस सरकार की प्रतिभूति हो उस सरकार द्वारा जारी की गयी उसी अवधि की अथवा लगभग उसी परिपक्वता अवधि की किसी प्रतिभूति पर प्राप्य प्रतिफल तथा अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए उचित समझी गयी राशि के अनुसार किया जायेगा ;

(ग) जहां, किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बंधपत्र अथवा अन्य विनिधान का बाजार मूल्य असामान्य बातों द्वारा प्रभावित होने के कारण उचित नहीं समझा जा सकता है, वहां ऐसे विनिधानका मूल्यांकन किसी उचित अवधि में उसके औसत बाजार मूल्य के आधार पर किया जाएगा ;

3079 GI/06-2

(घ) जहां किसी प्रतिभूति, शेयर, डिबेंचर, बंधपत्र अथवा अन्य विनिधान का बाजार मूल्य निर्धारण योग्य नहीं है, वहां केवल उसी मूल्य को, यदि कोई हो, हिसाब में लिया जाएगा जिसे ऐसी प्रतिभूतियों इत्यादि को जारी करनेवाले समुत्थान की वित्तीय स्थिति, पिछले पांच वर्षों में संदाय किए गए लाभांश तथा अन्य सुसंगत बातों को भी ध्यान में रखते हुए उचित समझा जाए;

(ङ) दावों का समाधान करने के लिए अपेक्षित परिसरों तथा अन्य सभी स्थावर संपत्तियों और अन्य आस्तियों का मूल्यांकन बाजार मूल्य पर किया जायेगा ;

(च) फर्नीचर और फिक्स्चर, स्टॉक में उपलब्ध लेखन-सामग्री तथा अन्य आस्तियों, यदि कोई हों, का मूल्यांकन बहियों में अपलिखित मूल्य पर अथवा वसूली योग्य मूल्य पर, जैसा भी उपयुक्त समझा जाए, किया जायेगा ;

(छ) अंतरिती बैंक द्वारा खरीदे और भुनाये गये बिलों सहित अग्रिमों, बही-ऋणों और विविध आस्तियों की संवीक्षा की जाएगी और प्रतिभूतियों और उनके जोखिमों को पूरा करने के लिए दी गयी गारंटियों की जांच और सत्यापन अंतरिती बैंक द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् अग्रिमों को उनके भाग भी है, दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जायेगा अर्थात् "लाभकर और तत्काल वसूलीयोग्य समझे गये अग्रिम" और "तत्काल वसूली योग्य न समझे गए अथवा वसूली के लिए अशोध्य और संदिग्ध समझे गये अग्रिम"।

(2) अंतरिती बैंक निर्धारित तारीख को "आस्ति खाता" के रूप में एक खाता खोलेगा। इस पैरा के अनुसार तत्काल वसूलीयोग्य आस्तियों के रूप में निर्धारित आस्तियों के मूल्य से संबंधित कुल राशि "आस्ति खाते" में जमा की जाएगी।

(3) (i) जहां किसी आस्ति का मूल्यांकन निर्धारित तारीख को अवधारित नहीं किया जा सकता है, वहाँ उसे भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन से, किसी पश्चातकथित तारीख को भागतः या पूर्णतः वसूली योग्य आस्ति समझा जाएगा ;

(ii) किसी आस्ति के मूल्यांकन अथवा किसी अग्रिम के वर्गीकरण अथवा किसी देयता के निर्धारण के संबंध में अंतरिती बैंक और अंतरक बैंक के बीच असहमति की दशा में उक्त मामला भारतीय रिजर्व बैंक के पास भेज दिया जाएगा, परंतु ऐसी राय प्राप्त होने तक उक्त मद या उसके किसी भाग का मूल्यांकन इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए अंतरिती बैंक द्वारा अनंतिम रूप में स्वीकार किया जाएगा ;

(iii) रिजर्व बैंक के लिए यह सक्षम होगा कि यदि ऐसा करना उसके लिए आवश्यक हो तो वह आस्ति की किसी ऐसी मद के मूल्यांकन या दायित्व की किसी ऐसी मद के मूल्य-निर्धारण/अवधारण के संबंध में उपयुक्त समझा गया कोई तकनीकी परामर्श प्राप्त करे और ऐसा परामर्श प्राप्त करने की लागत पूर्णतया अंतरक बैंक की आस्तियों में से संदेय होगी।

(4) दायित्व का अवधारणः इस स्कीम के प्रयोजनों के लिए दायित्वों में वे सभी आकस्मिक दायित्व सम्मिलित हैं जिन्हें निर्धारित तारीख को या उसके पश्चात् युक्तियुक्त रूप से उसके अपने संसाधनों से पूरा करने की अंतरिती बैंक से अपेक्षा कर सकेगा।

(5) पूर्वगामी उपबंधों के अनुसार अस्तियों का मूल्यांकन और दायित्वों का निर्धारण दोनों बैंकों और उनके सदस्यों तथा लेनदारों के लिए बाध्यकर होगा।

अध्याय - 3

लेनदारों और जमाकर्ताओं को भुगतान

6. अंतरक बैंक की दायित्व का निर्वहन:- (1) निम्नलिखित के संबंध में -

(क) अंतरक बैंक के किसी कर्मचारी द्वारा उस बैंक में कर्मचारिवृन्द निक्षेप के रूप में जमा की गयी किसी भी राशि का, विहित तारीख तक उस पर प्रोद्भूत ब्याज सहित, यदि कोई हो, पूर्ण संदाय किया जाएगा या उसके लिए उपबन्ध किया जाएगा ;

(ख) सावधि जमा, नकदी प्रमाणपत्र, मासिक निक्षेप, मांग या अल्प सूचना पर संदेय निक्षेप अथवा कोई अन्य निक्षेप, चाहे जिस नाम से हो, सहित अंतरक बैंक के पास प्रत्येक बचत बैंक खाते या चालू खाते के संबंध में अंतरिती बैंक विहित तारीख को तदनुरूप और वैसे ही खाता में संबंधित धारक (धारकों) के नाम से खोलेगा और इस योजना के अधीन संदेय सीमा तक ब्याज सहित पूर्ण राशि उसके खाते में जमा करेगा:

परंतु यह है कि जहां अंतरिती बैंक को किसी विशिष्ट खाते में की गयी प्रविष्टियों की शुद्धता के संबंध में उचित संदेह हो, वहां वह रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से उस खाते में जमा को निर्धारित तारीख से तीन मास से अनधिक के लिए रोक सकता है और इस अवधि में अंतरिती बैंक ऐसे खाते में सही बकाया राशि को सुनिश्चित करेगा।

(2) पैरा 5 के उप पैरा (4) के अधीन अवधारित अंतरक बैंक के प्रत्येक अन्य दायित्व के संबंध में अंतरिती बैंक जब देय हो लेनदारों को ऐसे दायित्व की राशि का संदाय करेगा।

(3) ब्याज वाले किसी भी जमा खाते के संबंध में अंतरिती बैंक, रिजर्व बैंक के निदेशों के अनुसार लागू दर पर विहित तारीख तक ब्याज का संदाय करेगा। किसी चालू खाते या बिना ब्याज वाले किसी अन्य खाते की शेष राशियों के संबंध में, खातेदार को कोई ब्याज संदाय नहीं किया जाएगा। कोई भी खातेदार 02 सितम्बर, 2006 से विहित तारीख तक की अवधि के दौरान अपने खाते से किसी निक्षेप या किसी अन्य धनराशि के भुगतान न होने पर किसी प्रतिकर के दावे का हकदार नहीं होगा।

(4) किसी संविदा में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, चाहे वह स्पष्ट वर्णित हो या निहितार्थ हो, अंतरिती बैंक में खोले गए किसी भी नये खाते के संबंध में ब्याज विहित तारीख से केवल उसी दर पर दिया जाएगा, जिस दर पर अंतरिती बैंक अपने जमाकर्ताओं को ऐसे खातों पर सामान्यतः ब्याज देता है और स्कीम के उपबंधों के अनुसार ब्याज जमा किया जाएगा।

(5) अंतरिती बैंक अंतरक बैंक में प्रत्येक पूर्ण चुकता शेयर के संबंध में अंतरक बैंक के सदस्यों जो विहित तारीख तक अंतरक बैंक में शेयरधारकों के रूप में रजिस्ट्रीकृत थे, को ऐसे शेयरों में उनके हितों के संबंध में उनके दावों को आंशिक रूप से संतुष्ट करने के लिए 28/- रुपए नकद (अट्ठाईस रुपए मात्र) अग्रिम का भुगतान करेगा।

(6) अंतरिती बैंक रजिस्ट्रीकृत शेयरधारक के नाम से अदाता के खाते में देय चेक के माध्यम से उप पैरा (5) के अधीन भुगतान करेगा तथा उसके रजिस्ट्रीकृत पते पर भेजेगा। इस उप पैरा के अनुसार भुगतान से उप पैरा (5) के अधीन भुगतान के संबंध में अंतरिती बैंक का पूर्ण उन्मोचन होगा।

(7) “आस्ति खाते” में जमा शेष का विनियोजन इस पैरा के अधीन अपेक्षित दायित्व को पूरा करने के लिए किया जाएगा। यदि आस्ति खाते में पर्याप्त शेष राशि नहीं है तो कमी की रकम अंतरिती बैंक द्वारा व्यय की गयी रकम मानी जायेगी और जहां तक संभव होगा, पैरा 7 के उप पैरा (7) में यथाउपबंधित के अनुसार वसूल की जायेगी।

अध्याय 4

7. अंतरक बैंक के सदस्यों के अधिकार और दायित्व:- (1) इस स्कीम के प्रारंभ होने पर अंतरक बैंक की समादत्त पूंजी और आरक्षितियों की संपूर्ण रकम जो पैरा 6 के उप पैरा (5) के अधीन किए गए भुगतान द्वारा कम की गई थी, अंतरक बैंक के अशोध्य और संदिग्ध तथा अन्य आस्तियों में अवक्षमण के लिए किये गये उपबंध के रूप में मानी जाएगी।

(2) अंतरक बैंक में प्रत्येक शेयर के संबंध में उस राशि को, जिसे विहित तारीख से ठीक पहले, प्रत्येक शेयरधारक द्वारा या उसकी ओर से शेयर पूंजी के लिए संदाय किया गया माना गया था जो 6 के उप पैरा (5) के अधीन किए गए भुगतान द्वारा कम की गयी थी, या उप पैरा (4) के अनुसरण में अंतरिती बैंक द्वारा मांगी गयी रकम के रूप में संदाय किया गया माना गया था, उसे “संग्रहण लेखे” के रूप में माना जायेगा और अंतरिती बैंक की बहियों में उसे उसी रूप में प्रविष्ट किया जायेगा।

(3) अंतरिती बैंक उस प्रत्येक व्यक्ति को, जो विहित तारीख को अंतरक बैंक के साधारण शेयर के धारक के रूप में रजिस्ट्रीकृत था (अथवा इस रूप में रजिस्ट्रीकृत करने के लिए हकदार माना गया होता), ऐसी तारीख अथवा तारीखों से जो विनिर्दिष्ट की जाएं तीन महीने में ऐसे शेयर अथवा शेयरों या बकाया रकम, यदि कोई हो, के संबंध में उसके द्वारा आसंदत्त रही मांगी न गयी रकम अदा करने को कहेगा।

(4) अंतरिती बैंक प्रत्येक दशा में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए व्यतिक्रम की अवधि के लिए छः प्रतिशत वार्षिक की दर पर ब्याज सहित उप पैरा (3) के अंतर्गत देय रकम की मांग और भुगतान को प्रवर्तित करने के लिए यथासंभव सभी उपाय करेगा।

(5) अंतरिती बैंक, अग्रिमों, खरीदे और भुनाए गये बिलों, बही ऋणों और विविध ऋणों तथा अन्य आस्तियों के संबंध में, जिन्हें 'आसानी से न वसूले जाने योग्य अग्रिम और/या वसूली के लिए अशोध्य और शंकास्पद' के रूप में वर्गीकृत किया गया है, या जो निर्धारित तारीख के पश्चात् पूर्णतः या भागतः वसूलीयोग्य हैं या हो सकते हैं, प्रत्येक दशा में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, मांग और भुगतान करने के लिए यथासंभव सभी उपाय करेगा और -

(क) देनदार या किसी अन्य व्यक्ति के साथ समझौता या व्यवस्था करेगा या ऐसे ऋण या आस्ति को अपलिखित करेगा ;

(ख) उसे अंतरित की गयी किसी प्रतिभूति या उसके द्वारा ली गयी किसी आस्ति का बिक्रय करेगा या अन्यथा व्यय करेगा।

(6) इसके अतिरिक्त, अंतरिती बैंक बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) की धारा 45ज के साथ पठित धारा 45ठ तथा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 543 के अधीन अंतरक बैंक के किसी प्रवर्तक, निदेशक, प्रबंधक या अन्य अधिकारी के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा क्षति के रूप में अधिनिर्णीत की गयी राशि की, यदि कोई हो, मांग या भुगतान करने के लिए प्रत्येक दशा में परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए यथासंभव सभी उपाय करेगा।

(7) अंतरिती बैंक उप पैरा (4), उप पैरा (5) और उप पैरा (6) में उल्लिखित मदों के कारण अपने द्वारा की गयी वसूलियों में से पहले वसूली के लिए किये गये खर्च के लिए विनियोजन करेगा और उसके बाद पैरा 6 के उप पैरा (7) में निर्दिष्ट कमी के लिए विनियोजन करेगा। यदि ऐसे विनियोग के पश्चात् कोई अधिशेष रहता है तो अंतरिती बैंक किसी आकस्मिक दायित्व तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से किसी अन्य दायित्व, चाहे आकस्मिक हो अथवा समग्र, जिसका अनुमान पैरा 5 के उप पैरा (4) में निर्धारण नहीं किया गया था और वह दायित्व निर्धारित तारीख के पश्चात् उद्भूत हुआ है या उसका पता चला है।

(8) उप पैरा (7) के निबंधनों के अनुसार विनियोग के पश्चात् यदि कोई अधिशेष राशि बचती है तो अंतरिती बैंक उस रकम में से अंतरक बैंक के पहले के शेयरधारकों यदि रकम के मद्दे कोई रकम उपलब्ध है, खातों में शोध्य रकम का समानुपातिक संदाय निम्नलिखित रीति और विनिर्दिष्ट सीमा तक होगा। यह भुगतान नीचे बताये गये ढंग से और निर्दिष्ट सीमा तक होगा :-

(क) पहले तो अंतरक बैंक के अधिमानी शेयरधारकों को देय राशियों, यदि कोई हों, के लिए तब तक संदाय करेगा, जब तक सभी खातों के बारे में पूरा संदाय न हो गया हो ; -

(ख) खण्ड (क) में उल्लिखित राशियों का पूर्ण भुगतान हो जाने के पश्चात् यदि कोई अधिशेष राशि अंतरिती बैंक के पास में बचेगी तो उसका समानुपातिक रूप से वितरण अंतरक बैंक के साधारण शेयरधारकों के बीच किया जाएगा :

परंतु यह शर्त है कि यदि कोई प्रश्न उद्भूत होता कि क्या उपर्युक्त उप पैराओं में उल्लिखित किसी खाते के प्रति कोई रकम शोध्य है तो यह प्रश्न रिजर्व बैंक को उसके विनिश्चय के लिए भेजा जायेगा।

(9) इस पैरा में निर्दिष्ट संग्रहण खातों को शोध्य रकम अंतरिती बैंक का दायित्व उसी सीमा तक समझा जाएगा, जिस तक इस स्कीम में उपबंध किया गया है।

(10) विहित तारीख से बारह वर्ष-की समाप्ति पर, अथवा ऐसी पूर्वत्तर अवधि जिसे केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट करे, इस पैरा के उप पैरा (5) में निर्दिष्ट किसी ऐसी मद का, जिसकी वसूली उस तारीख तक न की गयी हो, मूल्यांकन अंतरिती बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से किया जायेगा तथा अंतरिती बैंक उस मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए अवधारित किसी राशि या राशियों का वितरण पहले पैरा 5 के उप पैरा (4) में निर्दिष्ट दायित्वों का पूरा करने के लिए आवश्यक ऐसी किसी रकम की, जो उस तारीख को पूरी न की जा सकी हो, उससे कटौती करने के पश्चात् उप पैरा (8) में उपबंधित क्रम और रीति से करेगा।

अध्याय 5

अंतरक बैंक के कर्मचारियों के अधिकार और बाध्यताएं

8. कर्मचारियों की सेवाएं बनाए रखना :- (1) अंतरक बैंक के सभी कर्मचारी सेवा में बने रहेंगे तथा यह माना जायेगा कि उन्हें अंतरिती बैंक में उसी पारिश्रमिक तथा उन्हीं सेवा की शर्तों पर नियुक्त किया गया है, जो 2 सितम्बर, 2006 को कारोबार की समाप्ति से ठीक पहले उन कर्मचारियों को लागू थीं :

परंतु अंतरक बैंक के ऐसे कर्मचारियों ने, जिन्होंने विहित तारीख के ठीक पश्चात् एक मास की समाप्ति पर अंतरक बैंक या अंतरिती बैंक को किसी भी समय लिखित में दी गयी सूचना द्वारा अंतरिती बैंक के कर्मचारी न बनने के अपने आशय को सूचित कर दिया है, वे औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के उपबंधों के अधीन ऐसी प्रतिपूर्ति, यदि कोई हो, तथा ऐसे पेंशन, उपदान, भविष्य निधि और अन्य सेवा निवृत्ति के फायदों के हकदार होंगे जो 2 सितम्बर, 2006 को कारोबार की समाप्ति से ठीक पहले प्रवृत्त अंतरक बैंक के नियमों या प्राधिकारों के अधीन सामान्यतः उन्हें प्राप्त हो सकेगा।

(2) अंतरक बैंक, अंतरक बैंक के उन कर्मचारियों की बावत जिन्हें अंतरिती बैंक के कर्मचारियों के रूप में नियुक्त किया गया समझा गया है, उनके संबंध में यह भी माना जायेगा कि अंतरिती बैंक ने उनकी छंटनी संबंधी प्रतिपूर्ति का दायित्व भी ले लिया है। उस दशा में जब अंतरिती बैंक की सेवा में रहते हुए उनकी छंटनी की जाए

तो प्रतिपूर्ति का हिसाब इस आधार पर होगा कि उनकी सेवाएं निरंतर बनी रही थी और अंतरिती बैंक में उनके स्थानांतरण के कारण उनमें कोई व्यवधान नहीं आया है।

(3) उप पैरा (1) के अधीन सेवा में न रहने वाले कर्मचारियों को छोड़कर अन्य जिन कर्मचारियों की सेवाएं उप पैरा (1) के अंतरिती बैंक में जारी रहेंगी उन्हें अंतरिती बैंक इस स्कीम की स्वीकृति की विहित तारीख से तीन वर्ष से अनधिक अवधि के भीतर वही परिलब्धियां संचाय करेगा तथा वही सेवा शर्तें प्रदान करेगा जो अंतरिती बैंक के उसी श्रेणी या स्तर के तदनुसूची कर्मचारियों को लागू होंगी, परंतु यह इसके अधीन होगा कि अंतरक बैंक के उक्त कर्मचारियों की अर्हक और अनुभव अंतरिती बैंक के अन्य समतुल्य कर्मचारियों जैसी अथवा उनके समतुल्य हो :

परन्तु यदि इस संबंध में कोई संदेह अथवा मतभेद उत्पन्न हो कि उक्त कर्मचारियों में से किसी कर्मचारी की अर्हता अथवा अनुभव अंतरिती बैंक के उसी श्रेणी या उसी स्तर के अन्य कर्मचारियों की अर्हता तथा अनुभव के जैसा अथवा समतुल्य है या नहीं अथवा अंतरिती बैंक के वेतनमान में कर्मचारियों के वेतन के नियतन के लिए अपनाये जाने वाले सिद्धांतों अथवा प्रक्रिया के बारे में कोई संदेह अथवा मतभेद उत्पन्न हो तो ऐसे संदेह अथवा मतभेद को भारतीय रिज़र्व बैंक कोनिर्दिष्ट किया जायेगा, जिसका विनिश्चय अंतिम होगा।

(4) अंतरक बैंक के कर्मचारियों के लिए गठित यथास्थिति, किसी भविष्य निधि और उपदान निधि के न्यासी अथवा प्रशासक अथवा, अंतरक बैंक, निर्धारित तारीख के पश्चात् यथाशीघ्र अंतरिती बैंक के लिए गठित कर्मचारी भविष्य निधि और उपदान निधि के न्यासियों को अथवा अन्यथा, अंतरिती बैंक निर्देश दे, अंतरक बैंक के कर्मचारियों के फायदे के लिए न्यास में रखे हुए सारे धन एवं निवेशों को अंतरित कर देंगे :

परन्तु ऐसे पश्चात्कथित न्यासी, स्कीम आरंभ होने से पूर्व विनिधान के मूल्य में हुई किसी कमी अथवा किये गये किसी कार्य, उपेक्षा अथवा व्यतिक्रम की बावत दायी नहीं होंगे।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

9. **निक्षेपक या लेनदारों द्वारा मांग :-** अंतरक बैंक का कोई भी निक्षेपक अथवा लेनदार अंतरक बैंक अथवा अंतरिती बैंक के विरुद्ध उसके प्रति अंतरक बैंक के किसी दायित्व के संबंध में स्कीम द्वारा विनिर्दिष्ट सीमा के सिवाय कोई भी मांग करने का हकदार नहीं होगा।

10. **केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, अंतरिती बैंक या अंतरक बैंक के विरुद्ध विधिक कार्यवाहिया :-** इस स्कीम के अनुसरण में सद्भाविक रूप से की गयी अथवा क्री जानेवाली किसी बात

के लिए केन्द्रीय सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक अथवा अंतरिती बैंक या अंतरक बैंक के विरुद्ध कोई भी वाद नहीं लाया जाएगा अथवा विधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

11. अंतरक बैंक की शाखाओं का पुनर्गठन :- अंतरिती बैंक को यह विकल्प होगा कि वह अपनी सुविधा के अनुसार अंतरक बैंक की शाखाओं का समेकन करे और अंतरक बैंक की हानि पर चल रही विद्यमान शाखाओं को बंद कर दे अथवा स्थानांतरित कर दे। उपरोक्त विकल्प का अंतरिती बैंक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से एक वर्ष के भीतर अपनाया जायेगा।

12. विवरण तथा जानकारी देना :- अंतरिती बैंक इस स्कीम के कार्यान्वयन के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय-समय पर अपेक्षित विवरण तथा जानकारी केन्द्र सरकार भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत करेगा।

13. सूचना की तामिल की रीति :- जब तक कि अंतरिती बैंक की बहियों में नया पता दर्ज न हो, तब तक अंतरिती बैंक द्वारा दिए जाने वाली अपेक्षित कोई सूचना अथवा अन्य सूचना यदि अंतरक बैंक की बहियों में दर्ज पते पर स्पीड पोस्ट, कूरियर, पूर्व संदाय वाली सामान्य डाक अथवा अन्य माध्यम से प्रेषित की संबोधित भेजी गयी हो तो वह विधिवत् दी गयी सूचना समझी जायेगी तथा ऐसा नोटिस डाक द्वारा भेजे जाने के चार दिन के पश्चात तामिल की गयी समझी जाएगी। कोई सूचना या संसूचना जो सामान्य हित की हो, इसके अतिरिक्त एक या अधिक ऐसे दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापित की जायेगी जो उन स्थानों पर परिचालन में हो जहां अंतरक बैंक अपना कारबार कर रहा था।

[फा. सं. 15/7/2006-बीओए (ii)]

अमिताभ वर्मा, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2006

S.O. 1645(E).—Whereas on an application made by the Reserve Bank of India under sub-section (1) of section 45 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), the Central Government has made, under sub-section (2) of that section an order of Moratorium in respect of The United Western Bank Limited, Satara, Maharashtra;

And whereas during the period of Moratorium, the Reserve Bank of India, being satisfied that in the public interest and in the interest of the depositors so to do, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 45 of the said Act, had prepared a Scheme of Amalgamation of The United Western Bank Limited with Industrial Development Bank of India Limited.

And whereas the Reserve Bank of India, after having sent the said Scheme in draft to the banks concerned in accordance with the provisions of sub-section (6) of the said section and after having considered the suggestions and objections received in regard to the said scheme, had forwarded it to the Central Government for sanction;

NOW, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 45 of the said Act, the Central Government hereby sanctions the following scheme on and subject to the terms and conditions hereafter mentioned.

Chapter -1

Preliminary

1. **Short title and commencement:** (1) The Scheme may be called The United Western Bank Limited (Amalgamation with Industrial Development Bank of India Limited) Scheme, 2006.

(2) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, specify.

2. **Definitions:** In the Scheme, unless the context otherwise requires --

(1) "Act" means the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

(2) "Asset Account" means a notional account opened pursuant to sub-paragraph (2) of paragraph 5 of the Scheme for the purpose of ascertaining the surplus or shortfall after adjustment from time to time of liabilities of the transferor bank as provided in the Scheme;

(3) "Collection Account" means a notional account opened in accordance with paragraph 7 of the Scheme, for the purpose of ascertaining the amount, if any, available for distribution to the members of the transferor bank after adjustment of assets and liabilities;

(4) "prescribed date" means the date which the Central Government may specify under sub-paragraph (2) of paragraph 1;

(5) "Scheme" means The United Western Bank Limited (Amalgamation with Industrial Development Bank of India Limited) Scheme, 2006;

3079 GH/06-4

- (6) "transferor bank" means The United Western Bank Limited, a banking company having its Registered Office at Satara, Maharashtra – 415 001;
- (7) "transferee bank" means the Industrial Development Bank of India Limited, a banking company having its Registered Office at IDBI Towers, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.
- (8) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meaning respectively assigned to them in the Act.

Chapter - II

Transfer of business, properties, assets and liabilities

3. Transfer of assets and liabilities and general effect thereof: (1) On and from the prescribed date, all rights, powers, claims, demands, interests, authorities, privileges, benefits, assets and properties of the transferor bank, movable and immovable, including premises subject to all incidents of tenure and to the rents and other sums of money and covenants reserved or contained in the leases or agreements under which they are held, all office furniture, loose equipments, plant apparatus and appliances, books, papers, stocks of stationery, other stocks and stores, all investments in stocks, shares and securities, all bills receivable in hand and in transit, all cash in hand and on current or deposit accounts (including money at call or short notice) with banks, bullion, all book debts, mortgage debts and other debts with the benefits of securities, or any guarantee therefor, all other, if any, property rights and assets, benefit of all guarantees in connection with the business of the transferor bank shall, subject to the other provisions of the Scheme, stand transferred to, and become the properties and assets of the transferee bank; and on and from the prescribed date, all the liabilities, duties and obligations of the transferor bank shall be and shall become the liabilities, duties and obligations of the transferee bank to the extent and in the manner provided hereinafter.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing provisions, all contracts, deeds, bonds, agreements, powers of attorney, grants of legal representation and other instruments of whatever nature subsisting or having effect immediately before the prescribed date shall be effective to the extent and in the manner

hereinafter provided against or in favour of the transferee bank and may be acted upon as if instead of the transferor bank, the transferee bank had been a party thereto or as if they had been issued in favour of the transferee bank.

(3) If on the prescribed date any suit, appeal or other legal proceedings of whatever nature by or against the transferor bank is pending, the same shall not abate, be discontinued or be in any way prejudicially affected, but shall, subject to the other provisions of the Scheme, be prosecuted and enforced by or against the transferee bank:

Provided that where a contravention of any of the provisions of any Act or of any rule, regulation, direction or order made thereunder has been committed by, or any proceeding for a criminal offence has been instituted against, a director or secretary, manager, officer or other employee of the transferor bank before the prescribed date, such director, secretary, manager, officer or other employee shall, without prejudice to the application of section 6 of the General Clauses Act, 1897 (10 of 1897), be liable to be proceeded against under such law and punished accordingly as if the transferor bank, being a banking company had not been dissolved.

(4) If according to the laws of any country outside India, the provisions of the Scheme, by themselves, are not effective to transfer or vest any asset or liability situated in that country which forms part of the undertaking of the transferor bank to or in the transferee bank, the affairs of the transferor bank in relation to such asset or liability shall, on the prescribed date, stand entrusted to the Chief Executive Officer for the time being of the transferee bank and the Chief Executive Officer may exercise all powers and do all such acts and things as would have been exercised or done by the transferor bank for the purpose of effectively transferring such assets and discharging such liabilities. The Chief Executive Officer shall take all such steps as may be required by the laws of any such country outside India for the purpose of effecting such transfer or vesting and in connection therewith, the Chief Executive Officer may, either himself or through any person authorized by him in this behalf, realise any assets or discharge any liability of the transferor bank and transfer the net proceeds thereof to the transferee bank.

4. Closure of books of the transferor bank and preparation of balance sheet:

(1) The books of the transferor bank shall be closed and balanced and balance sheet prepared in the first instance as at the close of business on the 2nd September, 2006 and thereafter as at the close of business on the date immediately preceding the prescribed date and the balance sheet shall be got audited and certified by a chartered accountant or a firm of chartered accountants approved or nominated by the Reserve Bank of India for the purpose.

(2) A copy of the balance sheet of the transferor bank prepared in accordance with the provisions of the foregoing paragraph, shall be filed by the transferor bank with the Registrar of Companies as soon as possible after it has been received and thereafter the transferor bank shall not be required to prepare balance sheet or profit and loss accounts, or to lay the same before its members or file copies thereof with the Registrar of Companies or to hold any board meeting or annual general meeting for the purpose of considering the balance sheet and accounts or for any other purpose or to comply with the provisions of section 159 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and it shall not, thereafter, be necessary for the Board of Directors of the transferor bank to meet as required by section 285 of that Act.

5. Valuation of assets and determination of liabilities: The transferee bank shall, in consultation with the transferor bank, value the assets and reckon the liabilities of the transferor bank in accordance with the following provision; namely:

(1)(a) Investments, other than Government Securities, shall be valued at the market rates prevailing on the day immediately preceding the prescribed date;

(b) (i) The Government Securities shall be valued as on the day immediately preceding the prescribed date in accordance with the

principles laid down in the notification issued by Reserve Bank of India for the purpose of section 24 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949);

- (ii) The Securities of the Central Government such as Post Office Certificates, Treasury Savings Deposit Certificates and any other securities or certificates issued under the small savings scheme of the Central Government shall be valued at their face value or the encashable value as on the said date, whichever is higher;
- (iii) Where the market value of any Government Security such as the Zamindari Abolition Bonds or other similar security, if any, held by the transferor bank in respect of which the principal is payable in installments is not ascertainable or is, for any reason, not considered as reflecting the fair value thereof or as otherwise appropriate, the security shall be valued at such amount as is considered reasonable having regard to the installments of principal and interest remaining to be paid, the period during which such installments are payable, the yield of any security issued by the Government to which the security pertains and having the same or approximately the same maturity, and other relevant factors;
- (c) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investment is not considered reasonable by reason of its having been affected by abnormal factors, the investment may be valued on the basis of its average market value over any reasonable period;
- (d) Where the market value of any security, share, debenture, bond or other investments is not ascertainable, only such value, if any, shall be taken into account as is considered reasonable, having regard to the financial position of the issuing concern, the dividends paid by it during the preceding five years and other relevant factors;
- (e) Premises and all other immovable properties and any assets acquired in satisfaction of claims shall be valued at their market value;

(f) The furniture and fixtures, stationery in stock and other assets, if any, shall be valued at the written down value as per books or the realizable value as may be considered reasonable;

(g) Advances, including bills purchased and discounted, book debts and sundry assets, will be scrutinized by the transferee bank and the securities, including guarantees, held as cover therefor examined and verified by the transferee bank. Thereafter the advances, including portions thereof, will be classified into two categories namely, "Advances considered good and readily realizable" and "Advances considered not readily realizable and/or bad or doubtful of recovery".

(2) The transferee bank shall open on the prescribed date an account styled as "Asset Account". The aggregate amount representing the value of the assets determined as readily realisable assets in accordance with this paragraph shall be credited to the "Asset Account".

(3) (i) Where the valuation of any asset cannot be determined on the prescribed date, it may, with the approval of the Reserve Bank of India, be treated partly or wholly as an asset realisable at a later date;

(ii) In the event of any disagreement between the transferee bank and the transferor bank as regards the valuation of any asset and/or the classification of any advance and/or the determination of any liability, the matter shall be referred to the Reserve Bank of India, for its opinion, provided that until such an opinion is received, the valuation of the item or portion thereof by the transferee bank shall provisionally be adopted for the purpose of the Scheme;

(iii) It shall be competent for the Reserve Bank of India, in the event of its becoming necessary to do so, to obtain such technical advice as it may consider to be appropriate in connection with the valuation of any such item of asset or determination of any such item of liability, and the cost of obtaining such advice shall be payable in full out of the assets of the transferor bank.

(4) Determination of liability:- Liabilities for the purposes of the Scheme shall include all contingent liabilities which the transferee bank may reasonably be expected or required to meet out of its own resources on or after the prescribed date.

(5) The valuation of the assets and the determination of the liabilities in accordance with the foregoing provisions shall be binding on both the banks and the members and creditors thereof.

Chapter III

Payment to creditors and depositors

6. Discharge of liability of the transferor bank: (1) In respect of: -

(a) any sums deposited by any employee of the transferor bank with that bank as staff security deposits, together with interest, if any, accrued thereon up to the prescribed date shall be paid or provided for in full;

(b) every savings bank account or current account or any other deposit account including a fixed deposit, cash certificate, monthly deposit, deposit payable at call or short notice or any other deposits by whatever name called with the transferor bank, the transferee bank shall open with itself on the prescribed date a corresponding and similar account in the name of the respective holder(s) thereof crediting thereto full amount including interest to the extent payable under the Scheme:

Provided that where the transferee bank entertains a reasonable doubt about the correctness of the entries made in any particular account, it may with the approval of the Reserve Bank of India withhold the credit to be made in that account for a period not exceeding three months from the prescribed date within which the transferee bank shall ascertain the correct balance in such account.

(2) In respect of every other liability of the transferor bank determined under sub-paragraph (4) of paragraph 5, the transferee bank shall pay to the creditors the amount of such liability as and when they fall due.

(3) In respect of any interest bearing deposit accounts, the transferee bank shall pay interest at the rate applicable in accordance with the directives of the Reserve Bank of India till the prescribed date. In respect of balances in any current account or any other non-interest bearing account, no interest shall be payable to the account holder. No account holder shall be entitled to claim any compensation for the non-payment of any deposit or other money from his account during the period from the 2nd September, 2006 till the prescribed date.

(4) Notwithstanding anything to the contrary contained in any contract, express or implied, interest from the prescribed date shall be paid in respect of the new account opened with the transferee bank and credited in accordance with the provisions of the Scheme only at such rates as the transferee bank normally allows to its own depositors for such accounts.

(5) The transferee bank shall make an upfront payment in cash of Rs.28/- (Rupees twenty eight only) in respect of every fully paid-up share in the transferor bank, to the members of the transferor bank, who were, as on the prescribed date, registered as the holders of shares of the transferor bank, in partial satisfaction of their claim in respect of their interest in such shares.

(6) The transferee bank shall make the payment under sub-paragraph (5) by means of an account payee cheque drawn in the name of the registered shareholder and sent to his registered address. Payment in accordance with this sub-paragraph shall give a full discharge to the transferee bank with respect to the payment under sub-paragraph (5).

(7) The credit balance in the "Asset Account" shall be appropriated to the extent required to meet the liability under this paragraph. If the balance in the Asset Account is not sufficient, so much of the shortfall shall be treated as amount spent by the transferee bank and to the extent possible, be recovered by it as provided in sub-paragraph (7) of paragraph 7.

Chapter IV

- 7. Rights and liabilities of the members of the transferor bank:** (1) On the commencement of the Scheme, the entire amount of the paid-up capital and reserves of the transferor bank, as reduced by the payment made under sub-paragraph (5) of paragraph 6, shall be treated as provision for bad and doubtful debts and depreciation in other assets of the transferor bank.
- (2) In respect of every share in the transferor bank, the amount of which was treated as paid-up towards share capital by or on behalf of each shareholder immediately before the prescribed date, as reduced by the payment made under sub-paragraph (5) of paragraph 6, and / or the amount paid on account of the calls made by the transferee bank in pursuance of sub-paragraph (4) shall be treated as a "Collection Account" and shall be entered as such in the books of the transferee bank.
- (3) The transferee bank shall call upon every person who was, as on the prescribed date, registered as the holder of an ordinary share of the transferor bank (or would have been entitled to be so registered) to pay within three months from such date or dates as may be specified, the uncalled amount remaining unpaid by him in respect of such share or shares and the calls in arrears, if any.
- (4) The transferee bank shall take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts due under sub-paragraph (3) together with interest at six per cent. per annum for the period of the default.
- (5) The transferee bank shall in respect of the advances, bills purchased and discounted, book debts and sundry debts and other assets, which are classified as "Advances considered not readily realizable and / or bad or doubtful of recovery" or which are or may be realisable wholly or partly after the prescribed date, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce payment, and may -

3079 GI/06-6

(a) enter into a compromise or arrangement with the debtor or any other person or write off any such debt or asset;

(b) sell or otherwise dispose of any securities transferred to it or any asset taken over by it.

(6) The transferee bank shall, in addition, take all available steps having regard to the circumstances of each case to demand and enforce the payment of the amounts, if any, awarded as damages by the High Court against any promoter, director, manager or other officer of the transferor bank under section 45L of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), read with section 45H and also with section 543 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956).

(7) The transferee bank may appropriate the realisations effected by it on account of the items mentioned in sub-paragraphs (4), (5) and (6), in the first instance towards expenses incurred for the recovery of such amount and thereafter towards the shortfall referred to in sub-paragraph (7) of paragraph 6. If any surplus remains after such appropriation, the transferee bank shall make payment or provision in respect of any contingent liability as also with the prior approval of the Reserve Bank of India, in respect of any liability whether contingent or absolute which was not assessed in terms of sub-paragraph (4) of paragraph 5 and has arisen or been discovered after the prescribed date.

(8) If any surplus remains after the appropriation in terms of sub-paragraph (7), the transferee bank shall make payments pro rata from amount if any available towards the amounts, if any, due to the accounts of the former shareholders of the transferor bank in the manner and to the extent specified below-

(a) in the first place, the amounts, if any, due to the accounts of the former preference shareholders of the transferor bank till payment in full against all the accounts has been made;

- (b) after all the amounts mentioned in clause (a), have been paid in full, the surplus, if any, remaining in the hands of the transferee bank shall be distributed pro rata among the former ordinary shareholders of the transferor bank:

Provided that if any question arises whether any amounts are due against an account mentioned in any of the above sub-paragraphs, it shall be referred to the Reserve Bank of India for its decision.

(9) The amounts due to the collection accounts referred to in this paragraph shall be deemed to be a liability of the transferee bank only to the extent provided for in the Scheme.

(10) On the expiry of twelve years from the prescribed date or such earlier period as the Central Government after consulting the Reserve Bank of India may specify for this purpose, any item referred to in sub-paragraph (5) of this paragraph which may not have been realized by that date shall be valued by the transferee bank in consultation with the Reserve Bank of India and the transferee bank shall distribute any amount or amounts determined in the light of that valuation, after deducting therefrom first any such amount necessary for meeting the liabilities referred to in sub-paragraph (4) of paragraph 5 which may remain unsatisfied as on that date, in the order and the manner provided in sub-paragraph (8).

Chapter V

Rights and obligations of the Employees of Transferor Bank

8. **Continuation of services of the employees:** (1) All the employees of the transferor bank shall continue in service and be deemed to have been appointed in the transferee bank at the same remuneration and on the same terms and conditions of service, as were applicable to such employees immediately before the close of business on the 2nd September, 2006:

Provided that the employees of the transferor bank, who have by notice in writing given to the transferor bank or the transferee bank at any time before

3079 GE/06-7

the expiry of one month next following the prescribed date intimated their intention of not becoming employees of the transferee bank, shall be entitled to the payment of such compensation, if any, under the provisions of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) and such pension, gratuity, provident fund and other retirement benefits as may be ordinarily admissible under the rules or authorizations of the transferor bank as in force immediately before the close of business on the 2nd September, 2006.

(2) The transferee bank shall, in respect of the employees of the transferor bank who are deemed to have been appointed as employees of the transferee bank, be deemed also to have taken over the liability for them of retrenchment compensation in the event of their being retrenched while in the service of the transferee bank on the basis that their service has been continuous and has not been interrupted by their transfer to the transferee bank.

(3) The transferee bank shall, not later than the expiry of the period of three years from the date on which the scheme is sanctioned, pay or grant to the employees of the transferor bank whose services are continued in the transferee bank under sub-paragraph (1), except such of the employees who cease to be in service under the proviso to sub-paragraph (1), the same remuneration and the same terms and conditions of service as are applicable to the employees of corresponding rank or status of the transferee bank subject to the qualifications and experience of the said employees of the transferor bank being the same as or equivalent to those of such other employees of the transferee bank:

Provided that if any doubt or difference arises as to whether the qualifications or experience of any of the said employees are the same as or equivalent to the qualifications and experience of the other employees of corresponding rank or status of the transferee bank or as to the procedure or principles to be adopted for the fixation of pay of the said employees in the scales of pay of the transferee bank, the doubt or difference shall be referred to the Reserve Bank of India whose decision thereon shall be final.

(4) The trustees or administrators of any provident fund and gratuity fund constituted for the employees of the transferor bank, or as the case may be, the transferor bank, shall on or as soon as possible after the prescribed date transfer to the trustees of the employees' provident fund and gratuity fund constituted for the transferee bank or otherwise as the transferee bank may direct, all the moneys and investments held in trust for the benefit of the employees of the transferor bank:

Provided that such latter trustees shall not be liable for any deficiency in the value of investments, or in respect of any act, neglect or default done before the date of commencement of the Scheme.

Chapter VI

Miscellaneous

9. **Demand by Depositors or Creditors:** No depositor or creditor of the transferor bank shall be entitled to make any demand against the transferor bank or the transferee bank in respect of any liability of the transferor bank to him except to the extent specified by the Scheme.
10. **Legal proceedings against the Central Government, Reserve Bank of India, Transferee bank or Transferor bank:** No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government, the Reserve Bank of India or the transferee bank or the transferor bank for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of the Scheme.
11. **Reorganisation of branches of the transferor bank:** The transferee bank shall have the option of integrating branches of the transferor bank according to its convenience and may close down or shift the existing loss making branches of the transferor bank. The aforesaid option will, however, be exercised by the transferee bank with the prior approval of Reserve Bank of India, within a period of one year.
12. **Furnishing statement and information:** The transferee bank shall submit to the Reserve Bank of India such statements and information as may be

required by the Reserve Bank of India from time to time regarding the implementation of the Scheme.

- 13. Manner of service of notice:** Any notice or other communication required to be given by the transferee bank shall be considered to be duly given if addressed and sent by speed post or by courier or by pre-paid ordinary post or otherwise to the addressee at the address registered in the books of the transferor bank, until a new address is registered in the books of the transferee bank, and such notice shall be deemed to be served on the expiry of four days after it has been posted. Any notice or communication, which is of general interest shall be advertised, in addition, in one or more daily newspapers, which may be in circulation at the places where the transferor bank was transacting its business.

[F. No. 15/7/2006-BOA(ii)]
AMITABH VERMA, Jt. Secy.